

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या:- 123/17 (RCMS No. 2017/00135) (76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. मु0 केशर पत्नि बजरंगा जाति मीना निवासी ग्राम बौरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर
2. भरत लाल पुत्र बजरंगा जाति मीना निवासी ग्राम बौरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. बदरी पुत्र भूरया जाति मीना निवासी ग्राम बौरदा
2. कैलाश पुत्र भूरया जाति मीना निवासी ग्राम बौरदा
3. रामविलास पुत्र भूरया जाति मीना निवासी ग्राम बौरदा
4. विजयराम पुत्र मथुरा जाति मीना निवासी ग्राम बौरदा
5. सीताराम पुत्र मथुरा जाति मीना निवासी ग्राम बौरदा
6. ग्राम पंचायत आदलवाडा कलां तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर
7. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर

तहसील चौथ का
बरवाड़ा जिला सवाई
माधोपुर

.....रैस्पोजेन्टस

अपील विरुद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर, चौथ का
बरवाड़ा निर्णय दिनांक 09.05.2012

उपस्थिति:-

1. श्री श्रीदास सिंह वकील अपीलान्ट
2. श्री भोला शंकर शर्मा वकील रैस्पोजेन्ट

निर्णय

दिनांक:-08.01.2018

यह अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 09.05.2012 के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम बौरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा के नामा0 सं0 70 बजरंगा पुत्र रामरतन की विरासत भरत लाल पुत्र बजरंगा एवं मु0 केशर वेवा बजरंगा के नाम सरपंच ग्राम पंचायत आदलवाडा द्वारा दर्ज की गई। इस नामा0 आदेश के विरुद्ध बदरी वगैरहा ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय की अपील पेश की थी कि विवादित आराजी में अपीलान्ट व रैस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2, 1/2 भाग के खातेदार थे। बजरंगा काफी वर्षों पूर्व लक्ष्मीपुरा तहसील उनियारा जिला टौंक में चला गया था उसकी भूमि को अपीलान्ट काशत करते चले आ रहे हैं। रैस्पोजेन्ट सं0 1 व 2 मु0 केशर व भरतलाल का कभी कब्जा नहीं रहा। बजरंगा ने भी कभी काशत नहीं की। बजरंगा ने अपने जीवनकाल में दिनांक 31.12.98 को अपीलान्ट

बदरी वगैरहा के नाम वसीयत कर दी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जाँच किये नामा० तस्दीक किया है। नामा० वसीयतनामे के आधार पर बद्री वगैरहा के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था। अतः अपील स्वीकार की जाकर नामा० निरस्त किया जावे तथा अपीलान्त बदरी वगैरहा के नाम नामा० दर्ज किया जावे। मु० केसर ने जबाब पेश किया तथा बजरंगा के वारिस होने के कारण नामा० सही दर्ज होना बताया तथा अपील खारिज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर यह माना कि बजरंगा ने अपीलान्त के पक्ष में वसीयत की है। नामा० दर्ज करते समय वसीयत की जांच नहीं की है। अतः अपील स्वीकार कर नामा० निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को रिमाण्ड करते हुये वसीयत की जांच कर जायज उत्तराधिकारियों के पक्ष में पुनः नामा० निर्णित करने के निर्देश दिये। इस निर्णय के विरुद्ध यह अपील पेश की है।

विद्वान वकील अपीलान्त का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया। विवादित आराजी उनकी पुश्तैनी आराजी है। इस तथ्य को रैस्पो० तकासमे के दावे में स्वयं स्वीकार करते हैं। पुश्तैनी आराजी का वसीयतनामा नहीं किया जा सकता है तथा लिखा हुआ वसीयतनामा महत्वहीन होता है। उनका तर्क है कि उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर में अपीलान्त ने रैस्पो० के विरुद्ध तकासमा का दावा पेश किया था जिसमें रैस्पो० ने वसीयतनामा का तथ्य प्रकट नहीं किया था इसलिये तथाकथित वसीयतनामा कूटरचित व फर्जी साबित हो जाता है। उक्त दावा 15.02.97 को डिक्री भी हो चुका है। अपीलान्त मृतक बजरंगा के प्रथम श्रेणी के वारिसान है जिनका हित पुश्तैनी आराजी में जन्म से ही है। ऐसी स्थिति में नामा० सही दर्ज किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलान्त ने अपील मियाद बाहर पेश की थी, देरी का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर अपील को अन्दर मियाद मानने में त्रुटी की है। उनका तर्क है कि वसीयत के संबंध में नामा० की फिसकल प्रोसीडिंग में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसके लिये दावा ही उपचार है। दावे में ही स्वत्व तय हो सकते हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो० का तर्क है कि विवादित आराजी पर बजरंगा का कभी भी कब्जा नहीं रहा। विवादित आराजी को रैस्पो० ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। बजरंगा ने रैस्पो० सं० 1 लगायत 3 के पक्ष में वसीयत की है। वसीयत के आधार पर नामा० दर्ज किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने नामा० तस्दीक करते समय जाँच नहीं की है। उनका यह भी तर्क है कि वसीयत उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में पेश की है। भरतलाल ने वसीयत के विरुद्ध किमीनल केस दर्ज किया था। जिसमें भरतलाल को न्यायालय में दावे के निर्णय के तहत कार्यवाही कराने के लिये स्वतंत्र व सक्षम बताया था तथा कार्यवाही ड्रॉप की गई थी। उनका तर्क है कि वसीयत पर उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तराधिकार व वसीयत की जाँच कर निर्णय के लिये रिमाण्ड किया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा से जाहिर है कि बजरंगा पुत्र रामरतन जाति मीना ने रैस्पो० सं० 1 लगायत 3 के पक्ष में दिनांक 31.12.98 को वसीयत कर दी थी, जो नोटेरी पब्लिक द्वारा दिनांक 31.12.98 को तस्दीक हुई है। बजरंगा की दिनांक 22.12.2001 को मृत्यु हो चुकी है। बजरंगा के फौत होने पर उसके वारिसान अपीलान्त के नाम नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक कर दिया गया। जबकि बजरंगा द्वारा रैस्पो० 1 लगायत 3 के पक्ष में वसीयत कर चुका था। चूँकि नामान्तरकरण दर्ज होने के समय वसीयत के संबंध में कोई जाँच नहीं की है। सरपंच ग्राम पंचायत आदलवाडा कलां तहसील चौथ का बरवाडा ने नामा० तस्दीक करते समय उत्तराधिकार के संबंध में कोई जाँच नहीं की है। जबकि उत्तराधिकार के संबंध में जाँच कर ही

नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाडा ने उत्तराधिकार व वसीयत की जाँच कर निर्णय के लिये रिमाण्ड किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्त की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.05.2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official